











# सम्पादकीय

## पसमांदा मुसलमान और बीजेपी का गुणा-भाग

भाजपा की चुनावी रणनीति में पसमांदा मुस्लिम हमेशा से रहे हैं। देखा जाए तो आकड़ों के हिसाब से यह वोट बैंक लोकसभा की सौं से अधिक सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में इसकी एक झलक प्रथानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमांदा मुस्लिमों का नाम लेते हुए दिखाई दी। बैठक में मोदी ने कहा था- ‘पार्टी को ‘सन्ह यात्राओं’ के जरिए ‘पसमांदा मुसलमानों’ का समर्थन हासिल करना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में नए-नए समीकरणों पर चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्वेषकों का मानना है कि पीएम मोदी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ट्रैक्टर रहे हैं और उन्होंने एक सोची-समझी रणनीति के तहत पसमांदा मुस्लिमों का जिक्र किया है। पीएम मोदी की हर बात का राजनीतिक मतलब निकाला जाना लाजमी है और इस बात की संभावना प्रबल है कि यह संकेत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप हो सकता है। यह पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी ने पसमांदा का जिक्र किया हो। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पसमांदा वर्ग बीजेपी के साथ है। उनके बयान के बाद से ही पार्टी नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं कि बीजेपी, मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग पसमांदा को लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी की अल्पसंख्यक साखा ने पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका भी तैयार कर लिया है। पार्टी नेताओं के हिसाब से इसके लिए यो सुनी योजना बनाई गई है। पहली योजना के तहत, केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समुदाय के निचले पायदान तक पहुंचाया जाएगा और दूसरी योजना के तहत, जिन जगहों पर पार्टी बहमत में है उन्हें पार्टी इकाइयों में जगह दी जाएगी। इसके अलावा, पार्टी ने पसमांदा समुदाय से आने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को सम्मानित करने और उनकी जयंती पर समारोह आयोजित करने की भी योजना बनाई है। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज के यूपी अध्यक्ष वसीम राझन ने कहा है कि आजादी के बाद पीएम मोदी पहले ऐसे

## सिविल सेवा परीक्षा पर उठते प्रश्न, प्रारंभिक परीक्षा की गुणवत्ता की पहेली सुलझाने का समय

इन दिनों संघ लोक से गो आयोग (यूपीएससी) की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा हो रही है। यह 25 सिंतंबर तक चलने वाली है। यह परीक्षा तीन चरणों में होती है- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इस अवसर पर यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पिछले वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा का कट 34% पार्कर्स 43.77 प्रतिशत की इतनी प्रतिष्ठित उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का इतना कम कट आफ मार्क्स आना सम्भानजनक है? यह हास्यास्पद बात है कि इसी परीक्षा के सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न-पत्र को मात्र वालीफाई करना पड़ता है, जो सीरेट के नाम से अधिक जाना जाता है और ऐसा करने के लिए 33 प्रतिशत अंक की जरूरत होती है। दूसरे प्रश्न-पत्र के रूप में यह बात बाबी है कि क्या



ले युवाओं के गिरते हुए शैक्षणिक प्रांतीभा के स्तर के कारण है? देखा देखा है, तब तो यह अत्यंत ताजनक है। कोई भी राष्ट्र चाहेगा उसके सर्वोच्च स्तरीय प्रशासन देश की अच्छी से अच्छी प्रतिभाएं दें। इसलिए इन सेवाओं को इतना कार्यक एवं प्रतिष्ठापूर्ण बनाया जाना चाहिए। यदि देश ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रणाली पर निर्भीत रहना से बचाना होगा, किन एक अच्छी बात यह है कि हमारा है नहीं। इसके प्रमाण के तौर पर मुख्य परीक्षा के कट आफ मार्क्स में गिरावट आई होती तो उसका प्रभाव मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इन दोनों पर पड़ता। आखिर प्रारंभिक परीक्षा के अंकों में इतनी कमी क्यों है इसका उत्तर बहुत साफ है और वह यह कि पिछले कुछ वर्षों से सामान्य अध्ययन के रूप में जिस तरह के उलटे-पलटे और कठिन प्रश्न-पूछे जा रहे हैं, सामान्य न होकर विशेष से भी विशेष हो गए हैं। उदाहरण के रूप में इस वर्ष 2018 में अफीका की एक शरणार्थी बस्ती बीड़ीबीड़ी के बारे में पूछा गया। जिन चार ग्रन्थों

आर्थिक चुनौतियों से लड़ने की सही नीति  
आम लोगों को राहत देने की आसान होती राह

इस समय जब पूरी दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन-ताइवान तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में अवरोधों की बजह से अर्थिक वित्तीय चुनौतियों और बढ़ती महंगाई से त्रस्त है, तब भारत में अपनाई गई विकेपूर्ण आर्थिक रणनीतियों से आम आदमी को राहत मिलती दिखाई दे रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी

बमुश्किल 1.4 प्रतिशत होता था, जबकि इस वर्ष 10.6 प्रतिशत एथनाल मिश्रण किया जा रहा है, जो लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। 2025 तक पेट्रोल में एथनाल मिश्रण का लक्ष्य 20 प्रतिशत रखा गया है। यहीं वर्ज है कि एथनाल के उपयोग में तेल विपणन कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आठ

हम पड़ाव आरबीआइ द्वारा भारत साथ डालर के संकट का सामना रहे और रहे रूस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चान के अलावा एशिया और फ्रीका के कई देशों के बीच वापरिक सौदों का निपटान रुपये किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण अर्थ भी है। इस परिप्रेक्ष्य में खुलीय है कि भारत और रूस

र आगे बढ़ रहा है। इससे को अंतरास्थीय स्तर पर के लिए अहम मुद्रा बनाने में लेहरी। इससे जहां व्यापार कम होगा, वही विदेशी मुद्रा टाटने की चिंता भी कम होगी। वैशिक आर्थिक एवं वित्तीय यों तथा वैशिक मांग में ता के बीच भारत में सरकार

ऐसे में खुदरा महागाई में तत्परता से और अधिक कमी लाने की जरूरत है। खुदरा महागाई को नियंत्रित कर इस वर्ष छह प्रतिशत और आगामी दो वर्षों में चार प्रतिशत तक लाने के लिए रेपो रेट में कुछ और वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को कम किया जाना उपयुक्त होगा। देश में अब कच्चे



12.41 प्रतिशत रहा, जबकि जुलाई माह में 13.93 प्रतिशत थी। देश में पेट्रोल और डीजल में एथनाल का मिश्रण बढ़ाकर भी ईंधन की कीमतों में कमी लाने का प्रयास सफल हुआ है। 2014 में पेट्रोल में एथनाल मिश्रण

# नियंत्रण से बाहर विदेशी तकनीकी कंपनियां, कैसे तय होगी इनकी जवाबदेही

एक ऐसे समय जब यूरोप, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि अमेरिका में भी बड़ी टेक कंपनियों की मनमानी और उनके एकाधिकार पर लगाम लगाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, तब भी भारत में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग गृहगल, फेसबुक समेत बड़ी टेक कंपनियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एवं गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के खिलाफ कदम उठाने पर काम जरिये पश्चिमी देश इन कंपनियों की कमज़ोर नस पर हाथ रखे रहते हैं और कंपनियों की डाटा सुरक्षा ही क्या, अन्य किसी मामले में भी सरकारी आदेशों के उल्लंघन की हिम्मत नहीं होती। बीते दिनों आयरलैंड ने यूरोपीय डाटा एवं निजता नियमों के उल्लंघन मामले में इंस्ट्रांग्राम पर करीब 3,100 करोड़ का हर्जाना लगाया। उसी इंस्ट्रांग्राम पर भारत में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर तमाम अपमानजनक पेज मिल जाएंगे। आयरिश सरकार वाट्‌सैप और फेसबुक पर 1.7 करोड़ यूरो

अपनाइ गई आर्थिक  
तेयां आम आदमी और  
वस्था के लिए राहतकारी  
है इह, लेकिन अभी भी खाद्य  
की उच्च महंगाई दर देश  
एक चुनौती बनी हुई है।

# तकनीकी जवाबदेही

हाता नहा दिखे रहा हा हा। हालाक इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग गगल, फेसबुक समेत बड़ी टेक कंपनियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एवं गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के खिलाफ कदम उठाने पर काम निजता नयमा के ३८८ धन मामल में इंस्टाग्राम पर करोड़ ३,१०० करोड़ का हजारा लगाया। उसी इंस्टाग्राम पर भारत में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर तमाम अपमानजनक पेज मिल जाएंगे। आयरिश सरकार वाट्सएप और फेसबुक पर १.७ करोड़ युरो

Digitized by srujanika@gmail.com



का जर्माना भी ठोक चुकी है। गत सप्ताह ही यूरोपीय संघ की अदालत ने गूगल की प्रवर्तक कंपनी अल्फाबेट पर 4.2 अरब डालर का जर्माना लगाया। इससे पहले दक्षिण कीरिया में अल्फाबेट और फेसबुक पर संयुक्त रूप से 7.1 करोड़ डालर का हर्जीना लगाया गया था। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने भी यूरोप की तर्ज पर ऐसा कानून बनाया है। कुछ दिन पहले ही चीन ने भी निझी सुरक्षा संरक्षण कानून लागू कर दिया। उसके उल्लंघन पर कंपनी के वैशिक राजस्व का पांच प्रतिशत तक जर्माना लगाया जा सकता है और संबंधित कंपनी का व्यापारिक लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ऐसी सूरत में न तो कोई कंपनी इस चीनी कानून का उल्लंघन करने की हिम्मत करेगी और न ही चीनी सरकार के किसी और दिशानिर्देश की अनदेखी कर

ले में भी ऐसा ही किया गया जपा से निकासित नेता नुपुर बाड़ी देशों से भी इंटरनेट पर भारत विरोधी ट्रैड गया था। इसमें स्वयंभूत कर मोहम्मद जुबैर का हाथ बैर और उनके जैसे लोगों ने गह प्रचारित किया कि कैसे मुदाय एक सिख अर्थदीप नए धृणास्पद अभियान चला नुपुर शर्मा मामले ने भी याया था कि खाड़ी देशों और नान से चलाए गए इंटरनेट ट्रैड स्वतः-स्फूर्त नहीं, बल्कि जिंश का हिस्सा थे। स्पष्ट भारत विरोधी ये तत्त्व किसी भार-पैर के मुद्दे को हवा देकर अस्थिर करने की कोशिश रहेंगे और उनसे लड़ने में क राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारगर नहीं होंगे। उनसे मामला अंतरराष्ट्रीय बन गया था तो इतनी कार्रवाई हुई, लेकिन आंतरिक मोर्चे पर भी भारत की सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए ऐसे तमाम खतरे पैदा किए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर या तो सरकारें राजनीतिक कारणों से उदासीन रहती हैं या पिर लापरवाही के चलते अनभिज्ञ। जैसे ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष द्वारा आदि विश्ववेश्वर शिवालिंग मिलने का दावा किया गया तो इंटरनेट मीडिया पर शिवालिंग से जुड़ी ऐसी तमाम पोस्ट की गई, जो बहुत अपमानजनक थीं। इक्का-दुक्का मामलों को छोड़कर किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अर्थदीप प्रकरण में विकिपीडिया ने भले ही आपत्तिजनक सामग्री हटा दी, परन्तु ऐसे मामलों में बिग टेक कंपनियां अमूमन सरकारी आदेशों और भारतीय कानूनों का मखौल ही उड़ाती हैं।



